

>

Title: Need to allocate sufficient funds for execution of railway projects in a time bound manner.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): रेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न निर्माण परियोजनाएं समय-समय पर घोषित की जाती हैं तथा उनके लिए बजट आवंटन भी किया जाता है तथा लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता है। परंतु वास्तविकता में कुछ विशिष्ट परियोजनाएं छोड़कर किसी भी अन्य परियोजना के लिए न तो पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाती है न ही निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु ध्यान दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अरबों रुपये का नियोजन बिना किसी फल के काफी समय के लिए अनुपयोगी हो जाता है जिससे रेलवे की आर्थिक स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप यात्रियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। एक स्थिति यह भी निर्मित होती है कि परियोजनाओं की मूल लागत अंततः अत्यधिक वृद्धि के कारण कई गुना बढ़ जाती है और फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक लंबी अवधि तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे कई उदाहरणों में से मेरे क्षेत्र के कुछ उदाहरण यहां देना चाहूंगी।

इंदौर दाहोद परियोजना जब मूलतः स्वीकृत हुई थी तब उसकी मूल लागत दाहोद/गोधरा करीब 230 करोड़ रुपये आंकी गई थी पश्चात् संशोधित परियोजना इंदौर दाहोद जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 2008 में किया गया था जिसकी लागत 630 करोड़ रुपये आंकी गई व लक्ष्य सन् 2011 रखा गया था। इस परियोजना की वर्तमान लागत करीब 1700 करोड़ रुपये हैं तथा कार्य की स्थिति को देखते हुए आगामी 10 वर्षों में भी पूर्ण होने की संभावना नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि इस परियोजना पर अब तक व्यय की गई राशि का कुछ भी लाभ रेलवे को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी अनेक परियोजनाओं के अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं।

मैं यह आग्रह करना चाहूंगी कि परियोजनाओं की लागत को दृष्टिगत रखते हुए परियोजनाओं के लिए धनराशि का पर्याप्त आवंटन किया जावे तथा परियोजनाओं की प्राथमिकताएं भी निर्धारित की जावे व उस दृष्टि से उन्हें धनराशि आवंटित की जावे जिससे न केवल परियोजनाएं समयावधि में पूर्ण होगी वरन् उससे लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा।